RAJHIN/2014/55262

sancharjagat.com

खबरों व विज्ञापन
के लिए सम्पर्क करें
संचार जगत
मो.नम्बर:- +917357161599

संचार जगत
दैनिक समाचार पत्र
sancharjagat.com
editorial@sancharjagat.com

'सोच को इतना बड़ा रखो कि असफलता भी एक छोटा कदम लगे। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक दिशा है। बड़ा सोचो, बड़ा करो।'

वर्ष:13 | अंक: 291 जयपुर, मंगलवार, 24 नवम्बर 2026 मूल्य: 2.00 रूपए पृष्ठ : 4

ईएसआईसी ने पुराने नियम बदले, बीमारी और दुर्घटना पर सीधे खाते में आएगा पैसा

नई दिल्ली/संचार जगत

बीमारी, मातृत्व या काम के दौरान दुर्घटना के कारण काम नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और कार्यस्थल पर चोट लगने की स्थिति में मिलने वाला नकद लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा सकेगा। इसके लिए अलग से दावा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। इन शर्तों के पूरा होने पर पात्रता की जांच के बाद रकम सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजी जा सकेगी। हालांकि, कर्मचारी चाहें तो पहले की तरह ऑनलाइन या अन्य उपलब्ध माध्यमों से खुद भी दावा कर सकते हैं।

1950 के पुराने नियमों की जगह लेंगे नए प्रावधान



ईएसआईसी ने ''कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026'' अधिसूचित किए हैं। ये 1950 से लागू पुराने नियमों की जगह लेंगे। इसका उद्देश्य बीमित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। नए नियमों के तहत बीमारी और मातृत्व लाभ का भुगतान स्वत: किया जा सकेगा। इसके लिए तीन प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं।

- मेडिकल प्रमाणपत्र ईएसआईसी के सिस्टम से जारी होना चाहिए।
- नियोक्ता ने पोर्टल पर प्रत्येक महीने की जरूरी जानकारी जमा की हो।
- कर्मचारी का बैंक खाता और बीमा नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।

महिला कर्मचारियों को भी दी गई राहत

नए प्रावधानों में महिला कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। प्रसव की संभावित तारीख से पहले मातृत्व लाभ के लिए आवेदन करने की समय सीमा 50 दिन से बढ़ाकर 56 दिन कर दी गई है। वहीं, दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए यह अवधि 42 दिन निर्धारित की गई है।

दल-बदल कानून में सुधार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली/संचार जगत

- चुनाव आयोग, विधि आयोग और दो मंत्रालयों को भी नोटिस
- रणनीतिक इस्तीफों के जरिए अयोग्यता की कार्रवाई से बचने का मामला

दल-बदल विरोधी कानून के कथित दुरुपयोग और अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए जाने वाले रणनीतिक इस्तीफों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और विधि आयोग से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता ए. सेतु की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ राजनेताओं, सांसदों और अन्य लोगों की टिप्पणियों से न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हो रही है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंच सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मामला राजनीतिक दलों के एजेंडे से संबंधित नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन पर पडने वाले प्रभाव से जुड़ा है। उन्होंने विभिन्न नेताओं, सांसदों और एक पत्रकार के बयानों के साथ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। इस पर पीठ ने सवाल किया कि यदि मामला राजनीतिक दलों से संबंधित नहीं है तो याचिका में अलग-अलग घटनाओं को एक साथ क्यों जोड़ा गया है?

और चुनी हुई सरकारों के अस्तित्व पर संकट पैदा होने की आशंका रहती है। याचिका में मांग की गई है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होने या शुरू होने की आशंका के दौरान दिया गया इस्तीफा अपने आप इस कार्रवाई को समाप्त न करे।

विधानसभा अध्यक्ष और सभापति इस्तीफे की स्वैच्छिकता और वास्तविकता की जांच वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर करें तथा कारण सहित आदेश पारित करें।

▶ रिहायशी इलाकों में अवैध कमर्शियल गतिविधि पर राज्यों से मांगी रिपोर्ट

नगरीय निकायों के संरक्षण में ही फलते-फूलते हैं अवैध निर्माण: SC

पूरे देश में चल रही जनहित याचिकाओं के दायरे को किया सीमित, 6 जनवरी 2027 तक मांगे हलफनामे

नई दिल्ली/संचार जगत



रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण अक्सर नगर निकाय के अधिकारियों की मिलीभगत से ही फलते-फूलते हैं। कोर्ट ने राज्यों से भवन नियमों के पालन और नगर निकाय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत हलफनामे मांगे हैं। इसके लिए 6 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।

लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने की। पीठ ने कहा कि नगर निकाय भवन निर्माण नियमों को लागू करने में विफल रहे हैं। अवैध निर्माण के बाद होने वाली जांच महज औपचारिकता बनकर रह गई है। पीठ ने सवाल किया कि बिना भ्रष्टाचार के कोई मकान एक दिन में होटल और दूसरे दिन मॉल कैसे बन सकता है? जस्टिस नागरत्ना ने यह भी पूछा कि क्या भवन निर्माण नियमों और भूमि उपयोग के उल्लंघन की कोई कीमत तय है? सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में लंबित जनहित याचिकाओं का दायरा सीमित करते हुए स्पष्ट किया कि किसी एक संपत्ति से जुड़े विवाद या निजी हित के मामले को व्यापक जनहित याचिका के तहत अनिश्चितकाल तक नहीं चलाया जा सकता। निजी राहत चाहने वाले लोग नगर निकाय ट्रिब्यूनल या संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

न्याय मित्र ने बताई नौ त्रासदियां

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र एके सिन्हा ने स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण और रिहायशी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े घटनाक्रम के दौरान नौ त्रासदियां हुईं। इनमें दिल्ली की चार, लखनऊ और भोपाल की एक-एक घटना शामिल है। इन घटनाओं में करीब 100 लोगों की जान गई। सिन्हा ने दिल्ली और लखनऊ में आईआईटी के दो प्रोफेसरों की टीम की जांच का भी उल्लेख किया। उन्होंने आग्रह किया कि कानूनी चुनौतियों के बावजूद नगर निगम अधिकारियों को सीलिंग और तोडफ़ोड़ जैसी वैधानिक कार्रवाई जारी रखने दी जाए। साथ ही संपत्ति मालिकों के न्यायिक और अन्य संबंधित मंचों पर जाने के अधिकार को भी सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तोडफ़ोड़ का कोई आदेश नहीं दिया है।

भोपाल में 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस

भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों की पहचान की थी। 15 दिवसीय अभियान के दौरान इनमें से 8,084 को नोटिस जारी किए गए। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में निगम की कार्रवाई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से की गई। उन्होंने दावा किया कि सील की गई संपत्तियां दोबारा खोल दी गईं और प्रभावशाली उल्लंघनकर्ताओं को बचाया गया। स्थानीय निवासी इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ का रुख करने पर विचार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शहरी क्षेत्र साझा नागरिक संसाधन हैं। नियमों के उल्लंघन से सडक़, जल निकासी व्यवस्था, यातायात क्षमता और शहर के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 51(क) में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया। राज्यों के जवाबों पर विचार के बाद मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 को होगी। विस्तृत लिखित आदेश आना बाकी है।

भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश

मोदी क्षेत्र के दूसरे सबसे प्रभावी नेता

नई दिल्ली/संचार जगत

ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स-2026 में भारत को एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है। भारत का कुल पावर स्कोर बढक़र 40.5 अंक हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 0.5 अंक अधिक है। इस सूची में अमेरिका 78.9 अंकों के साथ पहले और चीन 73.6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान 38.6 अंकों के साथ चौथे और रूस 32.2 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। रिपोर्ट में भारत को प्रमुख शक्ति (मेजर पावर) का दर्जा दिया गया है।

भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्कोर भी बढ़कर 43.8 हुआ

भविष्य के संसाधनों के मामले में भारत को 56.2 अंक मिले हैं और वह इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। वहीं, रक्षा नेटवर्क में दो स्थान की बढ़त के साथ भारत नौवें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग और ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री ने इस सुधार में योगदान दिया है। भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्कोर भी बढक़र 43.8 अंक हो गया है। संस्कृति, सूचना के आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया है।

राजनीतिक दलों को एजेंडा उठाने से कैसे रोक सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट बोला- राजनीति रोकना हमारा काम नहीं, मामला सीजेआई को ट्रांसफर...

नई दिल्ली/संचार जगत



सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायपालिका के खिलाफ राजनेताओं और अन्य लोगों की कथित टिप्पणियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि राजनीतिक दलों को अपना एजेंडा उठाने से कैसे रोका जा सकता है? अदालत ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि इस तरह के मुद्दों को संसद में क्यों नहीं उठाया जाता और इनके लिए कानून बनाने की पहल क्यों नहीं की जाती।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ दो वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ राजनेताओं, सांसदों और अन्य लोगों की टिप्पणियों से न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हो रही है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा

ध्रुव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, आरएनएन। दिल्ली की साकेत अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले से जुड़ा है, जिसे विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने भाजपा आईटी सेल पार्ट-2 शीर्षक वाले वीडियो को लेकर दायर किया था। अदालत ने राठी की लगातार अनुपस्थिति और वारंट की तामील नहीं होने के बाद यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन रईस खान ने यह आदेश जमानती वारंट जारी होने के बावजूद राठी या उनके वकील के अदालत में पेश नहीं होने पर दिया।



भाजपा आईटी सेल पार्ट-2 वीडियो से जुड़ा है मामला

बच्चों की कस्टडी में माता और पिता से ऊपर उनका कल्याण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बच्चे कोई माता-पिता की संपत्ति या खिलौने नहीं हैं...

नई दिल्ली/संचार जगत

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे विवादों में माता-पिता के कानूनी अधिकारों से अधिक बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है।

बच्चे माता-पिता की संपत्ति या खिलौने नहीं हैं। अदालतों को कस्टडी का फैसला करते समय बच्चों की भावनात्मक, मानसिक और विकास संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दो नाबालिग बेटों की कस्टडी मां के पास बरकरार रखी और मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। दोनों बच्चों की उम्र 16 और 14 वर्ष है। वे मई 2014 से अपनी मां के साथ रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिता को बच्चों से नियमित मुलाकात का अधिकार भी दिया है। मामले के अनुसार, दंपती की शादी अगस्त 2009 में हुई थी और मई 2014 में दोनों अलग हो गए थे।

बच्चों ने मां के साथ रहने की जताई इच्छा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माता-पिता और बच्चों से बातचीत की। दोनों बेटों ने स्पष्ट मां के साथ रहने की इच्छा जताई। पीठ ने पाया कि मां ने अलगाव के बाद अकेले बच्चों की परवरिश की है और उनकी शिक्षा तथा देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। बच्चों का अपनी मां के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी है। कस्टडी का फैसला केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पिता प्राकृतिक अभिभावक हैं। अभिभावक नियुक्त करते समय बच्चे की उम्र, परिस्थितियों, पसंद, प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र और उसकी देखभाल करने की क्षमता पर विचार करना जरूरी है।

रक्षा बलों और सीएपीएफ के 14 व्हाट्सएप ग्रुप में पाक एजेंटों ने की घुसपैठ

नई दिल्ली/संचार जगत



- साइलेंट मेंबर बनकर चैट और दस्तावेजों पर रख रहे थे नजर
- सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के ऑडिट के दिए निर्देश

भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों की साइबर जासूसी की कोशिश का खुलासा किया है। पाक एजेंटों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रक्षा विभाग के नागरिक अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले करीब 13-14 निजी व्हाट्सएप ग्रुप में घुसपैठ की थी। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संबंधित ग्रुप और अन्य सोशल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का व्यापक ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध एजेंट भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर इन ग्रुपों में शामिल हुए थे। वे साइलेंट मेंबर के रूप में जुड़े रहते थे और ग्रुप में होने वाली बातचीत तथा साझा किए जाने वाले दस्तावेजों पर नजर रखते थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे संवेदनशील सुरक्षा कार्यों में तैनात कर्मियों को निशाना बनाकर चलाया जा रहा लक्षित साइबर जासूसी अभियान बताया है।

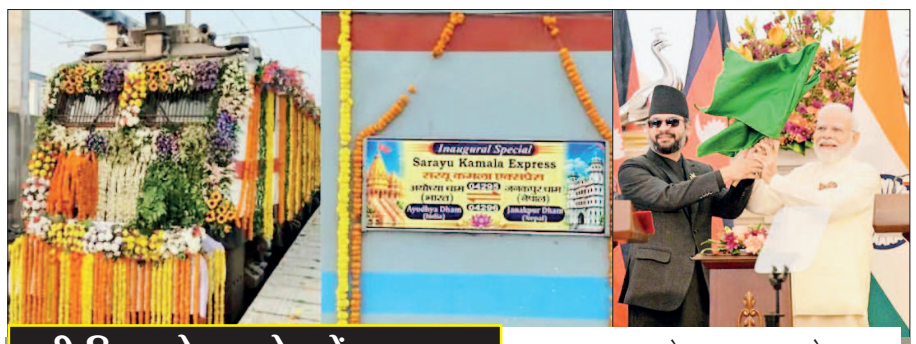
खुशखबरी प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दिखाई हरी झंडी, पहले सफर में 1,158 यात्री हुए सवार

अयोध्या-जनकपुर के बीच शुरू हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस

नई दिल्ली/संचार जगत

भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सरयू-कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम तक करीब 604 किलोमीटर की दूरी ट्रेन लगभग 19 घंटे में तय करेगी। आम यात्रियों के लिए इसका नियमित संचालन 28 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है।

अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन के पहले सफर में 1,158 यात्री सवार हुए। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ट्रेन करीब साढ़े तीन घंटे का सफर तय कर गोरखपुर पहुंची। इसका निर्धारित समय शाम 5:10 बजे था, लेकिन यह करीब 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। इसके बाद ट्रेन बिहार के विभिन्न स्टेशनों से होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई।



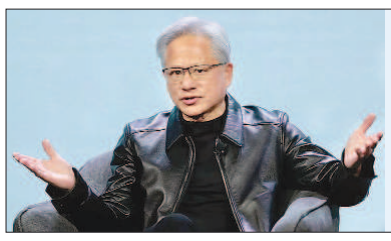
यूपी-बिहार के 10 स्टेशनों पर ठहराव

सरयू-कमला एक्सप्रेस का ठहराव अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी और जयनगर में होगा। जयनगर भारत में इसका अंतिम स्टेशन होगा। यहां यात्रियों के पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद ट्रेन नेपाल में प्रवेश करेगी। यात्रियों को बीच में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन दोनों दिशाओं में चलेगी। 17 कोच वाले एलएचबी रैक में आठ वातानुकूलित, सात स्लीपर, एक सीटिंग सह लगेज और एक पावर कोच शामिल होगा। पहली यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने ट्रेन शुरू होने पर खुशी जताई। यात्रियों का कहना था कि सीधी रेल सेवा से दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिल सकता है।

मोदी बोले- नेपाल के बिना हमारे राम और धाम अधूरे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था और संस्कृति पर आधारित हैं। भगवान राम और माता सीता दोनों देशों की साझा सभ्यता और आस्था के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि सरयू-कमला एक्सप्रेस की शुरुआत से इस पवित्र रिश्ते को नया आयाम मिलेगा। नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहीं, बालेन शाह ने भारत-नेपाल के रिश्तों को हिमालय की तरह अडिग और समुद्र की तरह व्यापक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को नया सुनहरा अध्याय देने की उम्मीद जताई। वहीं, बालेन शाह ने उन्हें नेपाल आने का न्योता दिया, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया।

11 दिन बाद फिर एनवीडिया के सीईओ बने जेन्सन हुआंग



अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा के बाद बोर्ड ने बदला अपना फैसला

नई दिल्ली/संचार जगत

दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सन हुआंग 11 दिन बाद फिर कंपनी के सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 12 नवंबर को इस्तीफा दिया था। इसके बाद कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा और हुआंग के साथ कई दौर की बैठकों के बाद उनकी वापसी का फैसला किया। बोर्ड के अध्यक्ष हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि कंपनी का नेतृत्व करने के लिए हुआंग सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों तथा ग्राहकों के हित में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हुए कहा एनवीडिया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए हुआंग का नेतृत्व जरूरी है।

संपादकीय

निकट आता नेपाल

नेपाल में बड़े पैमाने पर हिंसा और राजनीतिक उथलपुथल के बाद इसी वर्ष मार्च में वहां के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह की ओर से अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आना एक शुभ संकेत है। प्रथम विदेश यात्रा के लिए भारत को प्राथमिकता देना यह बताता है कि अंततः बालेन शाह को नई दिल्ली की महत्ता समझ आई।



इसका एक कारण पश्चिम एशिया संकट के कारण नेपाल की आर्थिक समस्याएं बढ़ना और हाल की विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही होना भी हो सकता है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत से संबंध सुधारने के लिए उत्सुक नहीं दिख रहे थे और यहां तक कि भारतीय विदेश सचिव से मुलाकात करने को भी तैयार नहीं थे।

हालांकि अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने चीन के बजाय पहले भारत आना तय किया, पर देखना यह होगा कि वे संतुलन बैठाने के लिए बीजिंग जाने की तैयारी तो नहीं करते? नेपाल को यह समझ आए तो अच्छा कि चीन से संपर्क बनाए रखने और अपने यहां उसके प्रभुत्व को बढ़ने देने में अंतर है। इस अंतर को कायम रखने से ही भारत-नेपाल मैत्री प्रगाढ़ हो सकती है और बालेन शाह की नई दिल्ली यात्रा से जो सकारात्मक वातावरण बना, वह संबंधों की मधुरता बढ़ा सकता है।

युवा नेपाली प्रधानमंत्री की नई दिल्ली यात्रा पर जो अनेक समझौते हुए और भारत ने नेपाल के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए अच्छी-खासी सहायता राशि देने के साथ उसे हरसंभव मदद देने की जो वचनबद्धता व्यक्त की, वह इसका प्रमाण है कि भारत उसका भरोसेमंद हितैषी बनने को तत्पर है। अब नेपाल का भी यह दायित्व बनता है कि वह भारत के हितों का ध्यान रखते हुए दोस्ती को मजबूत करने वाले कदम उठाए, क्योंकि अतीत में वहां संकीर्ण राजनीतिक कारणों से न केवल भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया, बल्कि उस चीन से नजदीकी बढ़ाई गई, जो हर देश में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है और केवल अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में रहता है। वह ऐसी ही कोशिश नेपाल के साथ भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी कर रहा है। केवल भूटान ही चीन के प्रभाव-दबाव में आने को तैयार नहीं।

नेपाल को इससे अवगत होना चाहिए कि चीन ने दोस्ती के बहाने किस तरह विभिन्न देशों के हितों पर चोट की है। यह स्वागतयोग्य है कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे भी अनेक समझौते हुए, जो दोनों देशों के बीच के आर्थिक रिश्तों के साथ सांस्कृतिक-धार्मिक संबंधों को बल देने और एक-दूसरे के प्रति सहयोग एवं भरोसा बढ़ाने वाले हैं।

चूंकि भारत और नेपाल में बहुत कुछ साझा है, इसलिए इसका कोई कारण नहीं कि दोनों देशों के बीच कोई खटपट हो और संकीर्ण इरादों से पैदा किए गए सीमा विवाद जैसे मामले संबंध सुधार में बाधक बनें।

गसच्चाई से मुंह मोड़ती आत्मकथा

गवे एक बेहद मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलने के उनके साहसिक और असाधारण निर्णय का श्रेय नहीं देतीं। इसके बजाय, वे इस उपलब्धि का सेहरा राजीव गांधी और बाद में मनमोहन सिंह के सिर बांधती हैं। उन्होंने इस वास्तविकता को भी अनदेखा कर दिया कि तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए राव ने न केवल मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, बल्कि उन्हें सभी कड़े फैसले लेने की पूरी आजादी भी दी। पूरे पांच साल तक राव मनमोहन सिंह की ढाल बने रहे। राव के ऐसे संरक्षण के बिना मनमोहन सिंह के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना संभव नहीं था।

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बीलोंगिंगःए जर्नी आफ लव' इन दिनों चर्चा में है। कहने को तो इसमें उनके जीवन से जुड़े संस्मरणों का समावेश है, लेकिन समग्रता में देखा जाए तो पुस्तक के रूप में उनका यह प्रयास नेहरू-गांधी परिवार की गलतियों पर पर्दा डालने और गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ने की कवायद ही अधिक है। इसमें बड़ी चतुराई के साथ जहां तमाम प्रमुख उपलब्धियों का श्रेय अपने परिवार को दिया गया, वहीं नरेन्द्र मोदी सहित परिवार से इतर प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों को अनदेखा किया गया। पुस्तक का सार यही है कि भारत ने जो भी प्रगति की, वह नेहरू-गांधी परिवार की मेहरबानी से ही संभव हुई। उन्होंने हरसंभव तरीके से अन्य प्रधानमंत्रियों के योगदान को उनके अपेक्षित श्रेय से वंचित ही रखा। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने बुनियादी ढांचे में जबरदस्त प्रगति की है। सरकार ने सामाजिक कल्याण की तमाम योजनाओं से भी देश को समृद्ध बनाया है। भारत को अब एक आर्थिक महाशक्ति और सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसके बावजूद सोनिया गांधी की 526 पन्नों की किताब में मोदी सरकार की उपलब्धियों के लिए प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं। दूसरी ओर, इस सरकार की उपलब्धियों का अवमूल्यन करने और उनका श्रेय नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी को देने के पुरजोर प्रयास किए गए हैं। अन्य प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों का श्रेय भी राजीव गांधी के खाते में डालने की सोनिया की इच्छा नरसिंह राव के मामले में ही स्पष्ट रूप से नजर आती है। वे एक बेहद मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलने के उनके साहसिक और असाधारण निर्णय का श्रेय नहीं देतीं। इसके बजाय, वे इस उपलब्धि का सेहरा राजीव गांधी और बाद में मनमोहन सिंह के सिर बांधती हैं। उन्होंने इस वास्तविकता को भी अनदेखा कर दिया कि तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए राव ने न केवल मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, बल्कि उन्हें सभी कड़े फैसले लेने की पूरी आजादी भी दी। पूरे पांच साल तक राव मनमोहन सिंह की ढाल बने रहे। राव के ऐसे संरक्षण के बिना मनमोहन सिंह के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना संभव नहीं था, लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने लिखा, 'राजीव ने उदारीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया था' और राव ने 'मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर तीव्र विकास के अगले दौर का मार्ग प्रशस्त किया।'सच यह है कि जब राव प्रधानमंत्री बने, तब भारत का खजाना खाली था। विदेशी मुद्रा समाप्त हो चुकी थी। उनके पूर्ववर्ती चंद्रशेखर ने 20 करोड़ डालर का कर्ज लेने के एवज में बैंक आफ इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रखा था, क्योंकि सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने तक के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। यह राव ही थे, जिनकी दृढ़ता से आर्थिक सुधारों की राह में अवरोध दूर हुए। अन्यथा नेहरू-गांधी परिवार के दौरान भारत कभी समाजवादी बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाता। राव ने जो दूरदर्शिता दिखाई, उसके चलते उनकी सरकार की विदाई के समय तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 50 अरब डालर तक पहुंच गया था। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 720 अरब डालर के स्तर पर पहुंच चुका है। फिर भी, सोनिया गांधी में इस सफलता का श्रेय राव को देने की उदारता का अभाव दिखता है। उलटे वे उनसे यह श्रेय छीनकर राजीव गांधी को देने की कोशिश करती हैं, जो अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान वामपंथियों-कम्युनिस्टों से डरे रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत में विदेशी मुद्रा का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। असल में भारत के समक्ष जिस भुगतान संतुलन का संकट पैदा हुआ था, वह राजीव गांधी की नीतियों का ही परिणाम रहा। दूसरों की उपलब्धियों पर अपना दावा ठोकने में कोई संकोच न करने वालीं सोनिया अपने परिवार या पार्टी की गलतियों का ठीकरा दूसरों पर बेबाकी से फोड़ती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने 'खून का बदला खून से लेंगे' का आह्वान किया, जिसके चलते सिखों का नरसंहार हुआ। रंगनाथ मिश्रा आयोग का निष्कर्ष था कि इस नरसंहार में 3,874 लोग मारे गए थे, जिनमें से अकेले दिल्ली में 2,307 लोगों की जान गई थी। उन दंगों में सिखों की संपत्तियों की बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की गई थी। अकेले दिल्ली में ही 131 गुरुद्वारों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। फिर भी तीन दिनों तक सेना नहीं नहीं बुलाई गई। तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एएस वैद्य ने आयोग को बताया कि दिल्ली में 6,000 सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद सेना को तत्काल नहीं बुलाया गया।



रंगनाथ मिश्रा आयोग और नानावटी आयोग दोनों ने ही यह निष्कर्ष निकाला था कि सिखों का यह नरसंहार कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित रूप से अंजाम दिया। यह सब साफ होने पर भी सोनिया अपने पति का बचाव करते हुए दावा करती हैं कि उन्होंने सेना को मोर्चा संभालने का आदेश दिया था, लेकिन जनरल वैद्य ने समय पर कदम नहीं उठाए।

जीवनशैली

महिला समानता दिवस

आधी आबादी की बराबरी से ही पूरी होगी तरक्की की तस्वीर



महिला समानता दिवस केवल अधिकारों की याद का दिन नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और निर्णय की स्वतंत्रता के उस संकल्प का प्रतीक है, जिसकी नींव लंबे संघर्षों से पड़ी।

हर वर्ष 26 अगस्त को 'महिला समानता दिवस' मनाया जाता है। यह दिन केवल महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करने का अवसर नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष, साहस और सामाजिक बदलाव को याद करने का दिन है, जिसने महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिलाने की दिशा में रास्ता बनाया। महिला समानता दिवस का मूल संदेश है कि समाज की प्रगति तभी वास्तविक मानी जा सकती है, जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संपत्ति, निर्णय-निर्माण और सम्मान के समान अवसर प्राप्त हों। यह दिवस लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता तथा समान भागीदारी सुनिश्चित करने के सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है।

मताधिकार से शुरू हुई बदलाव की बड़ी कहानी

महिला समानता दिवस का इतिहास अमेरिका के महिला मताधिकार आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में '19वां संविधान संशोधन' प्रभावी हुआ, जिसके बाद महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। यह उपलब्धि कई दशकों तक चले संघर्ष, आंदोलनों और सामाजिक सुधार अभियानों का परिणाम थी। हालांकि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना समानता की पूरी मंजिल नहीं था, लेकिन यह लोकतांत्रिक अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। बाद में 26 अगस्त को महिला समानता और अधिकारों के संघर्ष की स्मृति के रूप में विशेष महत्व मिला।

एक दिन, जिसने इतिहास की दिशा बदली

अमेरिका में इस दिन की औपचारिक पहचान भी महिला अधिकार आंदोलन की निरंतरता का हिस्सा रही। 1970 के दशक में महिला अधिकारों के लिए सक्रिय प्रयासों के बीच 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता देने की मांग मजबूत हुई। 1973 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस दिवस को मान्यता दी और इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से प्रतिवर्ष इसकी घोषणा की परंपरा विकसित हुई। समय के साथ यह दिवस महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से आगे बढ़कर शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, समान वेतन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नेतृत्व में भागीदारी जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ गया।

भारत में संविधान ने दी बराबरी की बुनियाद

भारत में महिला समानता का प्रश्न अपने सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने शुरुआत से ही महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध और अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएं लागू की गई हैं।

अधिकार मिलना ही नहीं, उनका इस्तेमाल भी जरूरी

महिला समानता का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार प्राप्त हों। वास्तविक समानता तब होगी, जब महिलाएं उन अधिकारों का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से उपयोग भी कर सकें। शिक्षा तक समान पहुंच, रोजगार के अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य सुविधाएं और अपनी पसंद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता समानता के महत्वपूर्ण आयाम हैं। घर के भीतर देखभाल और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी का समान बंटवारा भी लैंगिक समानता का अहम हिस्सा है।

कानून से आगे, सोच में बदलाव की जरूरत

तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद दुनिया के अनेक हिस्सों में महिलाओं को भेदभाव, हिंसा, असमान वेतन, बाल विवाह, शिक्षा से वंचित किए जाने और निर्णय-निर्माण में कम भागीदारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिला समानता दिवस समाज को यह याद दिलाता है कि कानूनों और नीतियों के साथ-साथ सामाजिक सोच में बदलाव भी जरूरी है। केवल महिलाओं को सशक्त बनाने से बात पूरी नहीं होगी; पुरुषों और संस्थाओं को भी समानता की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनना होगा।

नई पीढ़ी के कंधों पर बराबरी की जिम्मेदारी

महिला समानता दिवस नई पीढ़ी को यह समझने का अवसर देता है कि समानता किसी एक वर्ग को विशेष सुविधा देने का नाम नहीं, बल्कि सभी को समान सम्मान और अवसर देने का सिद्धांत है। बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान, लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती और घर-परिवार में समान जिम्मेदारी की शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। जब बेटियों और बेटों को समान सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता है, तभी समाज की प्रतिभा का पूरा उपयोग संभव होता है।

अतीत से जुड़ता आज...

फिर लौट रहा है पुराना फैशन, नई पीढ़ी को भा रहा विंटेज अंदाज

फैशन की दुनिया में बदलाव जितनी तेजी से आते हैं, उतनी ही तेजी से पुराने अंदाज भी नए रूप में लौटते हैं। आज की युवा पीढ़ी के बीच विंटेज कपड़े, पुराने दौर का संगीत और क्लासिक डिजाइन एक बार फिर लोकप्रिय हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें ज्यों का त्यों अपनाने के बजाय आधुनिक सोच और जरूरतों के साथ मिलाकर नया रूप दिया जा रहा है। यही वजह है कि बीते दशकों की चीजें आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक दिखाई दे रही हैं।

संगीत में पुराने सुरों की वापसी

फैशन के साथ संगीत में भी पुरानी धुनों का आकर्षण बढ़ा है। विनाइल रिकॉर्ड, पुराने हिंदी फिल्मी गीत, जैज, रॉक और रेट्रो पॉप को नई पीढ़ी नए उत्साह से सुन रही है। पुराने गीतों के रीमिक्स और नए कलाकारों द्वारा क्लासिक धुनों की नई प्रस्तुति ने इस रुचि को और मजबूत किया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भी पुराने संगीत को युवाओं तक आसानी से पहुंचा दिया है। अब किसी पुराने दौर का गीत खोजने के लिए रिकॉर्ड की दुकान तलाशना जरूरी नहीं।

विंटेज कपड़ों का नया आकर्षण

ढीली जींस, हाई-वेस्ट पैंट, प्रिंटेड शर्ट, पोल्का डॉट ड्रेस, पुराने अंदाज की जैकेट और चमड़े के बैग जैसे फैशन आइटम युवाओं को खासा आकर्षित कर रहे हैं। सेकेंड-हैंड और थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदे गए कपड़ों को नए परिधानों के साथ पहनना अब अलग और रचनात्मक शैली माना जाता है। कई युवा पुराने कपड़ों में मामूली बदलाव कर उन्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान से जोड़ रहे हैं। इस तरह विंटेज फैशन केवल पहनावा नहीं, बल्कि अपनी पसंद और व्यक्तित्व जाहिर करने का माध्यम बन गया है।



सोशल मीडिया ने बढ़ाया चलन

इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रेट्रो संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। युवा अपने पुराने कैमरों, विंटेज आउटफिट और रेट्रो संगीत के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं। इससे एक व्यक्ति की पसंद तेजी से ट्रेंड बन जाती है। पुराने फैशन को अपनाना अब केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि डिजिटल संस्कृति का हिस्सा भी बन चुका है।





डिजाइन में रेट्रो रंग

इंटीरियर और ग्राफिक डिजाइन में भी रेट्रो शैली की वापसी दिखाई दे रही है। पुराने पोस्टर, टाइपफेस, लकड़ी का फर्नीचर, रंगीन कांच और पारंपरिक पैटर्न आधुनिक घरों और कैफे में नए अंदाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिजिटल डिजाइन में भी पुराने कैमरा इफेक्ट, फिल्म ग्रेन और विंटेज रंगों का इस्तेमाल लोकप्रिय है। यानी तकनीक आधुनिक है, लेकिन उसकी प्रस्तुति में अतीत की छाप दिखाई देती है।

स्थिरता और अलग पहचान

विंटेज फैशन की लोकप्रियता का एक कारण पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता भी है। पुराने कपड़ों को दोबारा पहनना या थ्रिफ्ट करना नए कपड़ों की लगातार खरीदारी को कम कर सकता है। साथ ही, विंटेज चीजें हर व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान देती हैं। यही कारण है कि पुराना फैशन आज केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि रचनात्मकता, स्थिरता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का नया प्रतीक बन गया है।

अतीत और भविष्य का मेल

पुराने फैशन की वापसी बताती है कि शैली कभी पूरी तरह पुरानी नहीं होती। समय बदलता है, लेकिन अच्छी डिजाइन और संगीत अपनी जगह बनाए रखते हैं। नई पीढ़ी इन्हें आधुनिक जरूरतों और तकनीक के साथ जोड़कर एक ऐसी संस्कृति बना रही है, जिसमें अतीत की खूबसूरती और भविष्य की सोच साथ-साथ चलती है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की बैठक

निवाई टाइम्स



जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना के विभिन्न घटकों, वित्तीय प्रगति, पशुपालन उद्यमिता विकास कार्यक्रम, बकरी सीमेन प्रयोगशाला की स्थापना, पशुपालक प्रशिक्षण, चारा बीज उत्पादन तथा अनुसंधान परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए पशुपालकों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए ताकि पशुपालन क्षेत्र में रोजगार, उद्यमिता एवं उत्पांदन वृद्धि को प्रोत्साहन मिले। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य पशुधन एवं कुक्कुट क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, नस्ल सुधार, गुणवत्तापूर्ण चारा एवं चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान, नवाचार एवं पशुधन बीमा को बढ़ावा देना है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीतारामजी भाले ने बताया कि योजना के अंतर्गत बकरी, भेड़, सूकर एवं कुक्कुट पालन के साथ-साथ चारा उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

पुनर्मतदान में भी भाजपा को लगा झटका



संचार जगत

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों के बाद हुए पुनर्मतदान के नतीजों में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के 28 वार्डों में हुए पुनर्मतदान कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाते हुए 20 वार्डों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्ताधारी भाजपा महज 5 वार्डों पर सिमट गई। इसके अलावा 2 वार्डों पर निर्दलीय और 1 वार्ड पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। रिपोलिंग के नतीजे आने के साथ ही अब प्रदेश की सभी 37 जिला परिषदों के सभी 1,275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7,543 में से 7,542 वार्डों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। रिपोलिंग में तीन जिला परिषदों के 6 वार्डों में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जिला परिषदों के 62 प्रतिशत से अधिक और पंचायत समितियों के 50 प्रतिशत से ज्यादा वार्डों पर अकेले कांग्रेस ने जीत हासिल की है।

इसके मुकाबले भाजपा को जिला परिषदों के केवल 28.16 प्रतिशत और पंचायत समितियों के 29.41 प्रतिशत वार्डों में ही संतोष करना पड़ा है। पंचायतीराज चुनावों में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भी चिंता जताते हुए कहा कि चुनाव परिणाम अच्छे नहीं हैं और यह स्पष्ट संकेत है कि जनता हमसे नाराज है। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता की नाराजगी का मतलब है कि हमारे कामकाज में कोई न कोई कमी जरूर रही है।

भारतीय नौसेना की समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत

नौसेना को मिला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आशंक



संचार जगत

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में एक और स्वदेशी युद्धपोत जुड़ने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आशंक नौसेना को सौंप दिया। यह जीआरएसई का बनाया 120वां युद्धपोत है। खास बात यह है कि जीआरएसई ने महज 18 दिन के भीतर अपना दूसरा युद्धपोत नौसेना को सौंपा है। इससे पहले 5 नवंबर को अमिनी युद्धपोत की आपूर्ति की गई थी। आशंक' को पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में मुख्य स्टाफ अधिकारी रियर एडमिरल गौतम मरवाहा की मौजूदगी में नौसेना को सुपुर्द किया गया। आशंक नाम का अर्थ है निडरता और निर्भीकता। अपने नाम के अनुरूप यह युद्धपोत समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में भारतीय नौसेना की मदद करेगा। इसे इस युद्धपोत की आपूर्ति के साथ जीआरएसई अब तक 120 युद्धपोत बना चुका है। इनमें से 82 भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं।

एशिया के सबसे प्रभावी नेताओं में पीएम मोदी दूसरे नंबर पर

संचार जगत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित थिंक टैंक लोवी इंस्टिट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स फेहरिस्त में खास जगह दी है। उन्हें इस क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रभावी नेता बताया गया है। पीएम मोदी से ऊपर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के कूटनीतिक प्रभाव को उसकी प्रमुख ताकत बताया गया है। इस श्रेणी में भारत को 70.3 अंक मिले हैं। विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय नेतृत्व के आकलन में भी सुधार किया है। उन्हें तीन पायदान का उछाल मिला है और जिनपिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना गया है।

रिपोर्ट में भारत को प्रमुख शक्ति का दर्जा दिया गया है। 2026 एशिया पावर इंडेक्स में 27 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन 131 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें शक्ति से जुड़े आठ पैमानों को शामिल किया गया जिनमें आर्थिक और सैन्य क्षमता,



मजबूती, राजनयिक प्रभाव और आर्थिक संबंध शामिल हैं। भारत को इस सूचकांक में 100 में से 40.5 अंक मिले हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 0.5 अंक अधिक हैं। आर्थिक संबंधों के मामले में भी भारत की स्थिति बेहतर हुई है। इस श्रेणी में भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंचा है। क्षेत्रीय व्यापार और निवेश संबंधों में अपेक्षाकृत स्थिरता ने इसमें योगदान दिया है।

सरकारी स्कूलों की छात्राओं को मिलेगी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग

संचार जगत



जयपुर। प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित, निडर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजस्थान पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐतिहासिक पहल के तहत हाथ मिलाया है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की उपस्थिति में राजस्थान पुलिस और शिक्षा विभाग के बीच रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत प्रदेश के 36 हजार 765 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की 23.32 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान के तहत पुलिस विभाग सबसे पहले 11 हजार 701 ब्लॉक स्तरीय विद्यालयों के चयनित शिक्षकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद ये प्रशिक्षित शिक्षक मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी 36 हजार 765 सरकारी स्कूलों में जाकर छात्राओं को आत्मरक्षा की बारीकियां सिखाएंगे।

पुलिस ने आमजन की खोई हुई संपत्ति को लौटाने के लिए चलाया विशेष अभियान

33 लाख रुपये कीमत के 111 गुमशुदा मोबाइल बरामद



संचार जगत

कोटपूतली-बहरोड़। कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस ने आमजन की खोई हुई संपत्ति और उससे जुड़ी यादों को लौटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया।

पुलिस टीमों ने जिलेभर में तकनीकी सहायता और गहन तलाश के जरिए विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 111 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 33 लाख रुपये आंकी गई है।

जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने इन बरामद मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किया। एसपी सतवीर सिंह के निर्देशन में जिले की साइबर और पुलिस टीमों ने गुमशुदा मोबाइलों की ट्रैकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया।

इस पहल और त्वरित कार्रवाई से न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिली है, बल्कि आमजन के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ है।

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एसएमएस का होगा कायापलट

संचार जगत

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की करीब 90 साल पुरानी जर्जर इमारतों का अब पूर्ण कायापलट होने जा रहा है। मरीजों को अलग-अलग बिल्डिंगों में जांच और उपचार से निजात दिलाने के लिए अस्पताल का नया 30 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग, बांगड़ परिसर और नॉर्थ-साउथ विंग ओपीडी की पुरानी चार मंजिला इमारतों को तोड़कर उनकी जगह आईपीडी टावर की तर्ज पर 10 से 14 मंजिला तीन आधुनिक टावर बनाए जाएंगे। इस कार्य के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी पीडीकोर के साथ मिलकर देश की एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल डिजाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्म द्वारा सर्वे किया जा रहा है। योजना के तहत तीन चरणों में बनने वाले इन तीनों आधुनिक टावर में एक ही छत के नीचे सभी 25 विभाग जुड़ेंगे

रिश्वत मांगने का आरोपी एएसआई और कांस्टेबल थाने से हुए फरार

संचार जगत

उदयपुर। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक एएसआई पर थानाधिकारी हेमंत अहारी के नाम पर शराब ठेके के सेल्समैन से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत मिलते ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट अलसुबह करीब 3 बजे ऋषभदेव थाने जा पहुंची। हालांकि, एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी एएसआई रणजीत और कांस्टेबल कैलाश मीणा थाने से फरार हो गए।

पहाड़ों की बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन



संचार जगत

नई दिल्ली। पहाड़ों पर बदलते मौसम का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और भी जोर पकड़ेगी। इस हफ्ते न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की प्रबल संभावना है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के आसमान में कोहरे का डेरा रहने वाला है। मौसम में आ रहे इस बदलाव का सीधा असर एनसीआर की हवा पर पड़ेगा। ठंड के जोर पकड़ते ही और हवा की रफ्तार धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमा होने लगेंगे। फिलहाल, मौसम में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है और हवा कुछ हद तक साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ने की पूरी आशंका है।

पश्चिम बंगाल के नए नाम को मिली मंजूरी

संचार जगत



कोलकाता। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर पश्चिम बंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव को 9 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 14 दिसंबर तक चलेगा। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कोशिश सबसे पहले 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चे की सरकार ने शुरू की थी। उस समय राज्य का नाम बदलकर बंगला करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण उस समय यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य का नाम बंगाली में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी में बंगाल करने का प्रस्ताव किया था। हालांकि, उस समय केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी।

नवीन पटनायक ने विदेश यात्राओं पर लगे आरोपों को बताया झूठा

संचार जगत



भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजू जनता दल अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी, अपने करीबी वीके पांडियन और अन्य अधिकारियों की विदेश यात्राओं को लेकर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। मीडिया से बातचीत में नवीन पटनायक ने कहा कि मैंने विदेश की बहुत सीमित यात्राएं की हैं और वे केवल ओडिशा से जुड़े विषयों, वह भी बेहद महत्वपूर्ण विषयों के लिए थीं। मुझे समझ में आता है कि मेरी और मेरे अधिकारियों की यात्राओं को लेकर कुछ झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसका उचित जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनके करीबी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वीके पांडियन तथा आईपीएस अधिकारी रवि कांत की 2022-23 और 2023-24 के दौरान की गई विदेश यात्राओं की जांच के आदेश दिए थे। जांच सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरटीआई आवेदनों के जरिए जापान और इटली की यात्राओं पर हुए खर्च से संबंधित जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह संदिग्ध, अपारदर्शी और अधूरी है।

चोरी हुई 108 एंबुलेंस लावारिस मिली



संचार जगत

जोधपुर। सांचौर से चोरी हुई एक 108 एंबुलेंस जोधपुर के झालामंड क्षेत्र स्थित धरती आंगन सोसाइटी में लावारिस हालत में खड़ी मिली है। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके अंदर से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। आवासीय कॉलोनी में खड़ी चोरी की एंबुलेंस के भीतर अवैध हथियार मिलने की खबर फैलते ही सोसाइटी और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस महकमा भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पुलिस के अनुसार, बरामद की गई 108 एंबुलेंस सांचौर अस्पताल से चोरी हुई थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोरों ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए एंबुलेंस का जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया था और उसे जोधपुर लाकर झालामंड की धरती आंगन सोसाइटी में लावारिस छोड़कर फरार हो गए।

अभी चुनाव दूर, हाईकमान का फैसला होगा मंजूर : गहलोत

संचार जगत

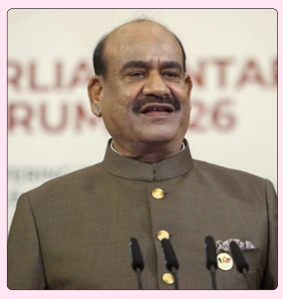


जयपुर। अशोक गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं पर कहा कि अभी चुनाव में दो साल बाकी हैं और यह फैसला हाईकमान का है। वहीं, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी द्वारा देश में जनता के लिए लगातार संघर्षों के कारण ही राजस्थान पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत मिली है। गहलोत ने कहा कि अभी चुनाव में दो साल बाकी हैं और ये काम हाईकमान का है। ये हमारा फैसला नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में चुनाव से पहले राज्य स्तर पर कभी ऐसे फैसले नहीं लिए गए हैं। हमेशा चुनाव के बाद फैसला होता है। चुनाव के बाद हाईकमान पर्यवेक्षक तय करके भेजता है। पर्यवेक्षक जनता और जनप्रतिनिधियों की राय पर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि रखकर फैसला होता है और उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं हो, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। जो भी फैसला हाईकमान करे, वो हम सबको मंजूर होना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

संचार जगत



जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई नेताओं ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आपके अनुभव, सहज व्यक्तित्व और संसदीय कार्यों की प्रतिबद्धता से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं



संचार जगत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समस्या लेकर पहुंचे लोगों से कहा कि चिंता मत करिए। सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराएगी।

मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। जो भी जरूरतमंद हैं, एस्टीमेट मिलते ही सरकार उनके लिए तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने पुलिस, राजस्व, शिक्षा, बिजली आदि से जुड़ी समस्याओं के प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों को प्रेषित कर समाधान के लिए निर्देशित किया।

जिला कलक्टर ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया अभियान का आगाज

संचार जगत

जयपुर। उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर रविवार को जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जेएलएन मार्ग स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदार पटेल पर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक मिलाकर तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया ।जिला कलेक्टर ने बताया कि जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय में निर्धारित भूतों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन जयपुर प्रथम में बूथ दिवस पर 148366 वहीं जयपुर द्वितीय में 192761 बच्चों को प्रतिरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि बूथ दिवस के बाद आगामी दो दिनों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों एएनएम आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के जिले के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक घर-घर जाकर पिलाई जाएगी। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे उनके 0 से 5 वर्ष तक के सही बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जयपुर प्रथम में अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए 790 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं इसके अतिरिक्त 140 यूनिट ट्रांजिट एवं 170 मोबाइल टीमें भी तैनात की गई है वही जयपुर द्वितीय में 816 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए इसके साथ ही 153 ट्रांजिट एवं 635 मोबाइल टीमें भी नियुक्त की गई है। जिला कलक्टर ने अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने भी भाग लिया। इस अवसर पर जयपुर द्वितीय में परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉक्टर रघुराज सिंह कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर सुरेंद्र गोयल और डॉक्टर प्रमिला मीणा ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई।



विकसित राजस्थान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण

सुशासन के लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही अनिवार्यः मुख्य सचिव



संचार जगत

जयपुर। विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में राजस्थान का सुशासन मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने एचसीएम रीपा के 70 वर्ष के अवसर पर आयोजित स्मृति व्याख्यान श्रृंखला में अधिकारियों को संवेदनशीलता, जवाबदेही, त्वरित निर्णय क्षमता एवं परिणामोन्मुखी कार्यशैली के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के साथ तकनीक आधारित नवाचारों के माध्यम से अंतिम छोर तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने प्रभावी और जवाबदेह शासन के लिए प्रशासनिक सुधार विषय पर अधिकारियों को सुशासन की कार्यप्रणाली और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि अमृतकाल भारत के रूपांतरण का महत्वपूर्ण कालखंड है। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में विकसित राजस्थान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नीति, वित्त एवं शासन, आधारभूत संरचना एवं संवहनीयता, विकास एवं रोजगार सृजन तथा समाज एवं जनकल्याण को सशक्त बनाने के चार-सूत्रीय दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और शासन व्यवस्था में आमजन का विश्वास मजबूत करना है।

इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही के साथ करना चाहिए।

राष्ट्रीय सचिवों का ट्रेनिंग कैंपः जयपुर में जुटेगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व

संचार जगत



जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने नवगठित संगठन को राज्यों में जिम्मेदारियां संभालने से पहले वैचारिक और रणनीतिक रूप से धार देने की तैयारी में जुट गई है। जयपुर के समीप बाड़ा पदमपुरा में 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों का 10 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले समापन सत्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। जयपुर ट्रेनिंग कैंप में खड़गे और राहुल गांधी के आगमन का कार्यक्रम अंतिम रूप से तय कर दिया गया है। इस कैंप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सचिन राव की टीम नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ और राजनीतिक प्रबंधन तथा कांग्रेस के पक्ष में सियासी नरेटिव तैयार करने के गुर सिखाएंगे। शिविर के लिए कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल 25 नवंबर को जयपुर आएंगे। बाड़ा पदमपुरा में पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो चुके हैं। करीब 23 वर्ष पूर्व साल 2003 में यहां कांग्रेस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया था।

राहुल गांधी सपने देखते रहें, पीएम मोदी फिर आएंगेः नितिन नवीन

संचार जगत



नई दिल्ली। तेलंगाना के करीमनगर में सेव डेमोक्रेसी, रिमूव एनार्की महा पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे, 2029 में लाल किले की प्राचीर से फिर नजर आएंगे।

उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि सपने देखते रहिए, देश का युवा, किसान, महिला, मजदूर और हर वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बार-बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन देश की जनता का समर्थन भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। करीमनगर की जनता ने भी अपने आशीर्वाद के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक रामलीला मैदान नहीं भर पाए, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 200 से अधिक स्थानों पर रामलीला मैदान से कहीं ज्यादा लोगों को एकत्र किया। विपक्ष ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा को लोकतंत्र का आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि जो लोग अपने हाथों में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि संविधान केवल हाथ में रखने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे दिल में है। राहुल गांधी और विपक्षी दल जुबान से संविधान की बात करते हैं, जबकि भाजपा संविधान को पूजती है और सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है।

भाजपा-अकाली गठबंधन पर सचिन ने किया प्रहार

सचिन पायलट ने कहा साढ़े पांच साल अलग रहे, अब कैसी मजबूरी

संचार जगत



अमृतसर। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के फिर से एक साथ आने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दोनों दलों पर तीखा हमला बोला।

पायलट ने कहा कि जिन कारणों से दोनों का गठबंधन टूटा था, क्या वे कारण अब खत्म हो गए हैं? साढ़े पांच साल तक एक-दूसरे पर ड्रग्स और तीन काले कानूनों को लेकर हमला बोलने वाली दोनों पार्टियां अब चुनाव से ठीक पहले मजबूरी में एक-दूसरे का दामन थाम रही हैं, क्योंकि पंजाब में दोनों अपनी जमीन तलाश रही हैं। पायलट ने कहा कि भाजपा हारने जा रही है। अभी राजस्थान में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, वहां लोगों ने एकतरफा वोट डाला है। एकतरफा वोट कांग्रेस को मिला है, इसलिए भाजपा का जाना तय है। मजबूरी में यह उनकी एक तरह की बेताब कोशिश है। अब वे अपने गठबंधन सहयोगी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले राजस्थान के लोगों ने भी अपनी राय दे दी है कि अब चिंतन करो। घमंड और अहंकार से काम नहीं चलेगा। भाजपा के डबल इंजन फेल हो चुके हैं। हम लोग बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाएंगे।

नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधान परिषद की ली शपथ



संचार जगत

पटना। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से नवनिर्वाचित आठ सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह परिषद सभागार में आयोजित किया गया।

विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय ने सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो नवनिर्वाचित सदस्यों राहुल राज और वंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण करने वाले सभी सदस्यों को उनकी शुभकामनाएँ हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को लेकर उनकी आपत्ति बरकरार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे लोग वकीलों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही एक बार फिर हम लोग शिकायत लेकर चेयरमैन साहब के पास जाएंगे। पटना हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं।

कानून और नियमावली के हिसाब से इन दोनों की सदस्यता जाएगी।

स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक

सीतारमण ने स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ की बजट पूर्व चर्चा

संचार जगत



नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट की तैयारियों के तहत स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जनजातीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुझाव लिए गए, ताकि आगामी बजट में इन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सके। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा, जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्रालय हर वर्ष बजट से पहले उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की परामर्श बैठकों का आयोजन करता है, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बजट में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के सुझावों को शामिल किया जा सके तथा देश की प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जा सके। इससे पहले वित्त मंत्री ने आवास, शहरीकरण और संस्कृति क्षेत्र और रोजगार और श्रम क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट परामर्श किया था।

स्वामित्व, प्रकाशक एवं संपादक : अवंतिका राठौड़ - पी.के. प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, 31, राम मंदिर के पास, पटेल नगर, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। कार्यालय : जे-17, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। संपर्क : 0141 463 7668
ई-मेल : sancharjagat@gmail.com| आरएनआई नं. : RAJHIN/2014/55262 समाचार चयन के लिए पीआरबी अधिनियम के तहत जिम्मेदार। न्यायाधिकार क्षेत्र : जयपुर महानगर।